

सूचना राजस्व विभाग प्रकीर्ण 6-24/91
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग

पत्र

विपत्ता युक्त एवं तयिवा राजस्व
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2

प्रति

समस्त मण्डला युक्त/उपायुक्त
हिमाचल प्रदेश

दिनांक शिमला-2, 9 जुलाई, 1991

विषय:-

सरकारी भूमि का एक विभाग से दूसरे विभाग को हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव

संदर्भ

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के, हाथिपा में बांधे गये पूर्व पत्रों का अधीक्षण करते हुए मुझे यह बताने का मिलना हुआ है कि सरकार ने मामले पर पुनर्विचार करके यह निर्णय लिया है कि सभी प्रकार की सरकारी भूमि राजस्व विभाग में जनहित है तथा जो भूमि एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग को हस्तान्तरित की जानी हो, के सम्बन्ध में विभिन्न अधिकारियों को स्वीकृति का प्रस्ताव निम्न प्रकार होगी। यह आदेश तत्काल लागू होगा:-

1. उपायुक्त 2-10-0 बीघा तक (अर्थात् बीघा तक)
2. मण्डला युक्त 2-10-00 बीघा से उपर 5-0-0 बीघा तक (अर्थात् बीघा से उपर पांच बीघा तक)
3. विपत्ता युक्त राजस्व 5-0-0 बीघा से अधिक पूर्ण शक्तिमा (पांच बीघा से अधिक)

उपायुक्तों तथा मण्डला युक्तों द्वारा जारी भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति पत्रों की प्रतिलिपि प्रत्येक पत्र में हिमाचल प्रदेश सरकार, राजस्व विभाग की सूचना में प्रेषित की जायेगी।

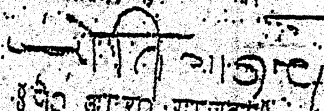
उक्त भूमि एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग को केवल जनहित कार्यों के लिए ही हस्तान्तरित की जायेगी।

यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी प्रकार की सरकारी भूमि राजस्व विभाग में जनहित है तथा जो जनहित कार्यों के लिए एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग को हस्तान्तरित की जानी हो, को इस पत्र पर हिमाचल प्रदेश के यदि कोई भूमि विभाग की आकांक्षा से अधिक हो जाये अथवा

हस्तांतरित भूमि को उसी प्रयोजन के लिये हस्तान्तरित नहीं किया जा रहा हो
जिले के लिए यह ही गई थी, तो अधिक प्रयोजन भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया सरकार,
राज्य विभाग को वापिस चली जावेगी।

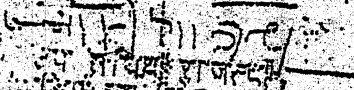
5. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि किसी सरकारी विभाग
को, प्रकृतिक काबजे में भूमि है, द्वारा सरकारी विभाग को यह भूमि हस्तांतरित
करने की आवश्यकता हो तो जनहित कारणों के लिए ऐसी भूमि हस्तांतरित करने के
साथ ही स्वीकृति देना सरकार को अग्रिम विचार जायेगी।

6. सरकार साथ ही यह भी निर्णय दोहराती है कि किसी भी तरह
में सुरक्षित भूमि को हस्तांतरित न किया जाये। इस संबंध में समय-समय
पर जारी आदेशों तथा अनुदेशों का तदानी से पालन किया जायेगा।

भवदीय,

जय भारत राज्याध्यक्ष
उप राज्यपाल
हस्तांतरण प्रक्रिया सरकार।

मुद्रांकन सं० राजस्व-डी॥जी॥6-24/91 दिनांक: निष्ठा-2, 9 जुलाई, 1991

प्रतिलिपि उप राज्यपाल, विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष सरकार को उनके मंत्र
संज्ञा संख्या 11-190/91 दिनांक 6-4-91 के तदानी से सुप्रसन्न प्रेषित है।


उप राज्यपाल
हस्तांतरण प्रक्रिया सरकार।

हासिल:

1. आर० 22-66/59 दिनांक 18-3-59
2. आर० 25-613/59 दिनांक 28-8-61
3. 4-14/72-रम-डी दिनांक 28-8-72
4. 4-20/72-रम-डी दिनांक 10-5-76
5. रम-डी 11/89-9/89 दिनांक 30-7-90
6. रम-डी 11/89-8/89 दिनांक 17-1-91

(11)

हिमाचल प्रदेश सरकार ।

राजस्व विभाग

सरकारी भूमि का हस्तांतरण / विक्रय ।

सरकारी भूमि को भारत सरकार के अधीन विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं/बोर्डों, सार्वजनिक उपकरणों आदि को हस्तांतरण/विक्रय किए जाने के मामलों में भूमि विक्रय का निम्नलिखित निर्धारण किया जाएगा ।

1. वित्तीयुक्त (राजस्व)

प्रचलित उच्चतम बाजारी कीमत के आधार पर 2 लाख रुपये मूल्य की सरकारी भूमि के बारे में मामले ।

2. राजस्व मंत्री

प्रचलित उच्चतम बाजारी कीमत के आधार पर 2 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक मूल्य की सरकारी भूमि के बारे में मामले ।

3. मुख्यमंत्री

प्रचलित उच्चतम बाजारी कीमत के आधार पर 3 लाख से अधिक मूल्य की सरकारी भूमि के बारे में मामले ।

अन्य सभी बातें यथावत रहेंगी ।

संयुक्त सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्या: राजस्व (डी)जी(8)24/91 दिनांक : शिमला 8.11.92
प्रतिलिपि निजी सचिव राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश शिमला-2

2. निजी सचिव मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ।
3. निजी सचिव राजस्व मंत्री हिमाचल प्रदेश ।

रैव0डी(जी)8-14/2015
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व-डी विभाग

प्रेषक:

अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रापिता:

1. भागस्त, गण्डलायुक्त,
हिमाचल प्रदेश
2. समस्त उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश

दिनांक शिमला-171002

9 फरवरी, 2016

विषय:-


सरकारी भूमि का एक विभाग से दूसरे विभाग को हस्तांतरण करने के बारे में।

संदर्भ:-

उपरोक्त विषय पर मुझे इस विभाग के पत्र संख्या रैव0डी(जी)-24/15 दिनांक 9.7.1991 की निरन्तरता में यह कहने का निर्देश हुआ है कि सरकार द्वारा यह निर्देश लिया गया है कि सरकारी भूमि का एक विभाग से दूसरे विभाग को हस्तांतरण करने संबंधी विभिन्न अधिकारियों को प्रदान शक्तियों में आंशिक संशोधन/बदलाव करते हुए भविष्य में ऐसे मामलों में भूमि हस्तांतरण के शक्तियां निम्न प्रकार होंगी :-

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. उपायुक्त | 1.00 हैक्टेयर |
| 2. गण्डलायुक्त | 1.00 हैक्टेयर से उपर 1.5 हैक्टेयर तक |
| 3. विभागाध्यक्ष (राजस्व) | 1.5 हैक्टेयर से अधिक पूर्ण शक्तियां
(माननीय राजस्व मंत्री की पूर्व अनुमति से) |

इसके अतिरिक्त अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


(प्रदीप कुमार टाक)
उप सचिव(राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार
फोन नं0 2628504

No. Rev-D(G)8-14/2015
Government of Himachal Pradesh
Revenue Department.

From

The Principal Secretary-cum FC(Revenue) to the
Government of Himachal Pradesh.

To

1. All Administrative Secretaries to the
Government of Himachal Pradesh.
2. All Divisional Commissioners in Himachal Pradesh.
3. All Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.

Dated: Shimla-2, 15th July, 2023

Subject:-

Instruction regarding transfer of Govt. land from one Department to
another Department in the State of Himachal Pradesh.

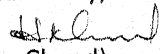
Sir,

In continuation to this Department letter No. Rev-D(G) 6-24/91 dated 9th July, 1991, letter No. Rev-D(G) 8-14/2015 dated 9th Feb., 2016 and in supersession of this department letter of even number dated 24th June, 2023 on the subject cited above, it has been decided by the Government after careful consideration of the matter that the following procedure/formalities may invariably be completed/followed with regard to the transfer of possession of Govt. land from one Department to another Department in the State of HP as under:-

1. Where the land in the possession/use of one department, is proposed for transfer in the name of other department of the State Govt., the NOC of that particular department only shall be necessary.
2. Where the land belongs to and possessed by the Govt. of HP and possession is proposed to be transferred to other departments of the State Govt. for any developmental activities, the NoCs from PWD, Jal Shakti Vibhag, Electricity Board, Forest Departments shall be necessary/obtained.
3. The NOCs of Local Bodies, i.e. Gram Panchayat, Nagar Panchayat and Municipal Corporation shall also be obtained. In case, if the concerned local bodies will not respond/issue NOC within a period of one month from receipt of request/reference from concerned Department/user agency, the user department/agency shall report the matter to concerned Deputy Commissioner who shall issue a notice to the concerned Local Bodies for assigning the reasons for not issuing such NOC. The reason, report/objections of the Local Bodies will be examined by the concerned DC's and decided by a well reasoned and speaking order within 10 days. The decision of the concerned DC shall be final and treated as NOCs of concerned Local Bodies for the proposed purpose.

It is, therefore, requested and impressed upon all concerned authorities that these instructions/procedure may be adhered to and followed strictly in land transfer cases in future accordingly. All such cases shall be routed through Div. Comm. and concerned AD respectively.

Yours faithfully,


(Balwan Chand)

Joint Secretary (Revenue) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone No. 0177-2880471